



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01072025-264277
CG-DL-E-01072025-264277

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 183]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 30, 2025/आषाढ़ 9, 1947

No. 183]

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 30, 2025/ASHADHA 9, 1947

श्रम और रोजगार मंत्रालय

(केन्द्रीय ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड)

संकल्प

नई दिल्ली, 30 जून, 2025

फा. सं. यू-23013/31/2014-एल.डब्ल्यू(बी).—ठेका श्रम (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड ठेका श्रम (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 की धारा 31 के अंतर्गत दिनांक 04.07.2001 की अधिसूचना सं. का.आ. 640 (अ) के आधार पर उक्त अधिसूचना की अनुसूची में दिए गए कार्यों में ठेका श्रमिकों के नियोजन के संबंध में पारादीप पोर्ट ट्रस्ट, ओडिशा के लौह और कोयला हैंडलिंग संयंत्रों को छूट देने पर विचार करने के लिए एतद्वारा एक समिति का गठन करता है।

2. समिति का गठन और इसके विचारार्थ विषय निम्नानुसार हैं:-

1. श्री सुरेंद्र कुमार पांडे,

-अध्यक्ष

भारतीय मजदूर संघ

मकान नं. 107 पो-विश्रामपुर कोलियारी,

जिला- सूरजपुर, छत्तीसगढ़।

2. श्री कुणाल रावत, -सदस्य
राष्ट्रीय सचिव, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस और
महासचिव राजस्थान राज्य समिति
ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस,
35-36, रणजीत नगर, खातीपुरा, जयपुर-302012।
3. कार्यकारी निदेशक, -सदस्य
सिविल इंजीनियरिंग, (सामान्य),
रेल मंत्रालय, (रेलवे बोर्ड),
कमरा संख्या 127, रेल भवन,
नई दिल्ली-110001।
4. श्री दिलीप कुमार चक्रवर्ती, -सदस्य
हाउस संख्या 322ए, भगवान दास चित्रकार हाटा,
हुमायूंपुर उत्तर,
गोरखपुर, उत्तर प्रदेश-273015।
5. उप मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) -सदस्य संयोजक
भुवनेश्वर, ओडिशा।

3. प्रस्तावित समिति के विचारार्थ विषय निम्न प्रकार से होंगे:-

"यह अध्ययन करना कि पारादीप पोर्ट ट्रस्ट में लंबित रिट याचिका की स्थिति क्या है, सभी हितधारकों के साथ परामर्श कर अधिसूचना एस.ओ. संख्या 640 (ई) दिनांक 04.07.2001 की अनुसूची में निर्दिष्ट कार्यों में पारादीप पोर्ट ट्रस्ट को छूट देने का औचित्य है, जो उक्त अधिसूचना की अनुसूची में दिए गए कार्यों में ठेका श्रमिकों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है।"

4. समिति का मुख्यालय भुवनेश्वर में होगा। समिति दो महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

जय भगवान, सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT**(Central Advisory Contract Labour Board)****RESOLUTION**

New Delhi, the 30th June, 2025

F. No. U-23013/31/2014-L.W(B).—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970, the Central Advisory Contract Labour Board hereby constitutes a Committee to consider the Grant of exemption in the iron and Coal handling plants of Paradip Port Trust, Paradip Port, Odisha under Section 31 of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970, against Notification S.O.No. 640(E) dated 04.07.2001 in respect of prohibit the employment of Contract Labour in the work given the schedule to the said Notification.

2. The composition of the Committee and its terms of reference will be as under:-

- | | |
|---|------------------|
| 1. Shri Surendra Kumar Pandey,
Bharatiya Mazdoor Sangh
Qutr. 107 Po-Vishrampur Koliyari,
District- Surajpur, Chhatisgarh. | -Chairman |
| 2. Shri Kunal Rawat,
National Secretary,
All India Trade Union Congress and
General Secretary Rajasthan State Committee
of All India Trade Union Congress,
35-36, Ranjeet Nagar, Khatipura, Jaipur-302012. | -Member |
| 3. The Executive Director,
Civil Engineering, (General),
Ministry of Railways, (Railway Board),
Room No. 127, Rail Bhawan,
New Delhi-110001. | -Member |
| 4. Shri Dilip Kumar Chakraborty,
House No. 322A, Bhagwan Das Chitrakar Hata,
Humayunpur North,
Gorakhpur, Uttar Pradesh -273015. | -Member |
| 5. Deputy Chief Labour Commissioner (Central)
Bhubaneshwar, Odisha. | -Member Convener |

3. The terms of reference of the proposed Committee would be as follows: -

“To study the status of pending writ petition, visit the Paradip Port Trust and consult with all the stakeholders, and see the working condition of contractor labour in Paradip Port Trust, against Notification S.O. No.640(E) dated 04.07.2001 prohibiting of employment of Contract Labour in the works given in the schedule (a) Muck Cleaning and (b) Spillage removal to the said Notification.”

4. The Headquarters of the Committee will be at Bhubaneshwar. The Committee shall submit its report within two months.

JAI BHAGWAN, Secy.